

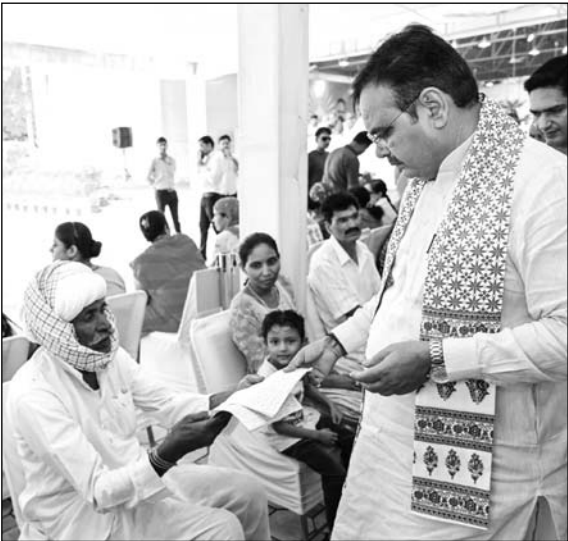
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जनसुनवाई बनी सुशासन की नई मिसाल

मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। शासन की सेवा का माध्यम मानते हुए यह सरकार

- जयराम और कैलाश को मिला कृषि विद्युत कनेक्शन**
- मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, अब नहीं सूख रही फसलें**

प्रदेशवासियों के हित के लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।



मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में समस्या का समाधान किया।

जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,

जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कोई परिवादी बीमारी में इलाज की मदद के लिए आते हैं तो कोई परिवादी अपनी पेंशन से जुड़े प्रकरण

को निस्तारण के लिए तो कोई विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

कोटपूतली के नारायणपुर तहसील निवासी जयराम किसान परिवार से हैं। उन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जोकि पिछले काफी समय से लंबित था। जनसुनवाई में अपने इस प्रकरण को लेकर जब जयराम आए तो मुख्यमंत्री ने फसलों के सीजन को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जयराम के कृषि कनेक्शन आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसी तरह अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के कैलाश चंद मीणा को भी कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को अपनी इस परेशानी से अवगत कराया।

कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के क-वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवार माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक

27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का क-वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर

के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं हैं। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करे सरकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे और जरूरत पड़ने पर उन्हें संशोधित करने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अनूठी परिस्थिति में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जस्टिस अनूप कुमार डंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेहर गंगिया के अपने पिता के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि उसके माता-पिता का मार्च, 2018 में विवाह हुआ था। इसके बाद वे आस्ट्रेलिया गए थे। जहां 1 जून, 2020 को याचिकाकर्ता का जन्म हुआ। इस पर वहां की सरकार ने नवंबर, 2021 में

- अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**
- याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**

याचिकाकर्ता को नागरिकता दे दी। इसके बाद वह भारत सरकार से वीजा लेकर अपने माता-पिता के साथ यहां आ गईं। इस दौरान उसकी समय-समय पर वीजा अवधि 24 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई। याचिका में कहा गया कि इस बीच याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया और उसकी मां ने याचिकाकर्ता के पिता पर कई केस कर दिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इमिग्रेशन ब्यूरो में याचिकाकर्ता की वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे ब्यूरो ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी मां ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की

जाएगी। इसलिए मामले में कोर्ट दखल देकर उसकी वीजा अवधि बढ़ाए। इसका विरोध करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो की ओर से अपी कहे गए। जस्टिस डी.एन. जयशंकर ने याचिकाकर्ता के ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई या उसे डिपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया में नागरिक है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

शिक्षा के साथ संस्कारों की सीख दे रहा है गायत्री परिवार: दिलावर

जयपुर। किरण पथ, मानसरोवर स्थित गायत्री वेदना निवारण केंद्र परिसर में मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रवेशोत्सव- 2025 बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गायत्री परिवार के इस विद्यालय ने बहुत कम समय में अच्छी तरक्की की है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा हुआ था तथा आज प्रवेश उत्सव भी मेरी उपस्थिति में हो रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक एवं राष्ट्रहित के कामों में सदा अग्रणी रहता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार सदैव समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजकीय विद्यालय में बड़ी तेजी से नामांकन व वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गुणात्मक प्रयास एवं नवाचारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। बच्चों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के



गायत्री परिवार के मां भगवती विद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्सव मनाया।

साथ शिक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी एवं राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि यह विद्यालय गायत्री परिवार द्वारा नि:शुल्क संचालित किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में

नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा व स्टाफिंग में खामियों को लेकर नोटिस जारी

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी

जयपुर/जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा शामिल हैं, ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा, स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नवोदय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत आर. दवे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कई नवोदय विद्यालयों में अब तक पूर्णकालिक वार्डन, काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी, परिधि सुरक्षा, आपात प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीपीसीआर, एनडीएमए द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य को उजागर

- जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं**
- विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है**

किया है जैसे कि दिसम्बर 2024 की शिक्षा के क्षेत्र में संसद की खासी समिति को भी उद्धृत किया है जिसके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है। यानी इन विद्यालयों में 24.77 प्रतिशत पदो की रिक्तियों को भरा नहीं गया है जबकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि रिक्तियों को जल्द भरा जाये। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2019 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को

अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बिच ही इन विद्यालयों में 49 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें से आधे एसएसी -एसटी वर्ग के थे। वही 2019 से 2023 के बीच 25 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा एसएसी -एसटी वर्ग का था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यादातर इन मौतों में कई मामलों में एफआईआर दर्ज है परन्तु कई मामलों में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इन विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है, और आये दिन इन मुद्दो पर प्रदर्शन किये जाते हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

विवाद बढ़ा तो ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत रेट घटाकर ले लिया पौधे सप्लाई का टैंडर

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम में पौधे सप्लाई के टैंडर में भारी गड़बड़झाला चल रहा है। "वन टाइम प्लान्टेशन" के लिए 10 फ़ीट पौधे देने के लिए ठेकेदारों ने पहले तो मात्र 5 प्रतिशत कम रेट डाली थी, परन्तु हैरिटेज निगम में 55 प्रतिशत कम दर आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इन्हीं फर्मों ने अपनी रेट 20 प्रतिशत तक घटाकर काम ले लिया।

अब चर्चाएं यह हो रही हैं कि आखिर हैरिटेज निगम से 35 फ़ीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों हैं? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे हैं। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध

करवाना संभव ही नहीं है। परन्तु सवाल यह उठ रहा है कि यह चिंता तो कम दर पर ठेके लेने वाले संवेदक को होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर निगम प्रशासन ने वन टाइम प्लान्टेशन कि निविदा के कार्यदिश "नेगोशिएशन" के बाद 20 प्रतिशत कम दर पर जारी किये हैं। यहाँ ठेकेदार ने 300 रुपए के 10 फीट के पेड़ 270 से 285 रुपए तक में देने की दर डाली थी, परन्तु जब हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक की रेट आयी तो बड़ा विवाद हो गया। तमाम विवादों के बावजूद ग्रेटर निगम प्रशासन ने यह कार्यादेश जारी करने का फैसला लिया। मजदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी इसी तरह ठेकेदारों से 160 से 170 रुपए के बीच खरीदे है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे है कि आखिर

ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, कनेर, हरसिंगार, शहतूत, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल हैं।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार "वन टाइम प्लान्टेशन" के 30 लाख रुपए से कम के टैंडर में भी कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थी, जिसके कारण "डी" श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

- जैसलमेर के फूसासर में 765 के.वी. में स्थापित होगा विद्युत उपकेन्द्र**

सरकार द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं।

इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले की भगियाणा तहसील के फूसासर में 765 के.वी. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा यह विद्युत उपकेन्द्र 80 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह निर्णय पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस उपकेन्द्र की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आमजन को सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

भाजपा रक्षाबंधन पर्व को सेवा, संगठन और समर्पण के रूप में मनाएगी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व को जनसहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता एवं सामाजिक समर्पण के साथ भव्य रूप में मनाने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता "रक्षा का यह पर्व, सामाजिक एकता और सेवा का अवसर" के मूलभाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक जिला महामंत्री एवं महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी संयोजक व सह प्रोजेक्ट के रूप में कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

8 अगस्त को सम्मान व समर्पण दिवस:

इस दिन पार्टी कार्यकर्ता टैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालयों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों सहित सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। बहनों द्वारा तिलक, राखी एवं मिष्ठान वितरण कर यह संदेश दिया जाएगा— आप हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं।

स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा भावना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9 अगस्त को संगठनात्मक एकता

व परिवार दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता इस दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बुध, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार — एक सूत्र में बंधा, संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव का संशक्त करेंगे।

10 अगस्त को सेवा व सामाजिक सद्भाव दिवस को भाजपा कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों को राखी भेजेंगे या उनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। साथ ही कच्ची बस्तियां, मजदूर बस्तियां, झुग्गी-झोपडियों और घुमंठू समाज के बीच जाकर राखी व मिठाई वितरित की जाएगी। यह दिन "रक्षा का धागा, सम्मान और अपनत्व का संदेश" लेकर सेवा और संवेदना का उत्सव बनेगा।

यह आयोजन सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा एवं मंडल स्तर पर आयोजित होगा। पूर्व तैयारी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।

भाजपा का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन-जन तक पहुंचाना है।

रक्षा सूत्र से बंधेगा भारत, एकता, सेवा और संस्कारों के साथ — यही है इस कार्यक्रम की मूल भावना।

जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ. निधि पटेल ने की समीक्षा बैठक

जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की नियमित माॉनिटिंग करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैमरों से कचरा फेंकने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएं।

जिससे कि सड़क पर कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएं। सीईओ निधि पटेल ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि शहर के प्रमुख बाजारों में देर रात तक खुलने वाली दुकानों से कचरा सड़क पर ही फेंका जा रहा है, जो कि सुबह तक सड़क पर ही पड़ा रहता है और ओपन डिपो का रूप लेकर शहर में सफाई व्यवस्था को खराब कर रहा है। इसलिए एगिनिगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मिलकर दोस प्लानिंग करें और उन दुकानों को चिह्नित कर समझाइश करें नहीं मानने पर भारी



जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ. निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की।

चालान वसूला जाएं। जिससे कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो।

वहीं समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ निधि पटेल ने स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत प्रोजेक्ट को समीक्षा की और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लाल डुंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण को लिए अपआएफ प्लान्ट के शुरू होने के लिए शीघ्र पॉल्यूशन पुनःओसी लेने और लंगडियावास में पौधरोपण करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी

के अधिकारी और नगर निगम हेरिटेज के जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बाजारों में कचरा संग्रहण के लिए चल रहे निगम के हूपर, व्यापारी हूपर में ही डालें कचरा वहाँ, सीईओ डॉ निधि पटेल ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज की ओर से समयानुकूल सभी बाजारों में हूपर चल रहे हैं। दुकानदार अपने कचरे को हूपर में ही डालें, सड़क पर कचरा नहीं फैलाएँ, जिससे कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो।